

वशेष: वशेष श्रेणी राज्य का दर्जा

संदर्भ एवं पृष्ठभूमि

इधर संसद में जसि मुद्दे की सरवाधकि चर्चा रही वह है तेलुगु देशम और वाईएसआर कांग्रेस द्वारा आंधर प्रदेश को वशेष श्रेणी राज्य (Special Category Status State) का दर्जा देने की मांग। इस मुद्दे पर गतरिध के कारण संसद में 15 दनि से कोई कामकाज नहीं हो पा रहा। इस मुद्दे पर तेलुगु देशम पार्टी NDA सरकार से अलग हो गई और उसके दो केंद्रीय मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। इसी मुद्दे पर सरकार के खलिाफ अवशिवास प्रस्ताव का नोटसि भी दिया गया है।

वदिति हो कि इससे पहले 2013 में बहिर ने भी वशेष श्रेणी राज्य का दर्जा देने की मांग की थी। इसके अलावा राजस्थान, झारखंड भी वशेष श्रेणी राज्य के दर्जे की मांग करते रहे हैं।

क्या है वशेष श्रेणी राज्य का दर्जा?

आज बेशक केंद्र सरकार का कहना है कि वह किसी राज्य को वशेष आर्थिक पैकेज तो दे सकता है, लेकिन वशेष श्रेणी राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। लेकिन पूर्व में किसी राज्य को वशेष श्रेणी राज्य का दर्जा देने के लिये कुछ मापदंड तय किये गए थे, जनिसे उनके पछिडेपन का सटीक मूल्यांकन कर उसके अनुरूप दर्जा प्रदान किया जाता था।

कसिे मलिता है (मापदंड)?

इसके मापदंडों में उक्त क्शेत्तर का पहाड़ी इलाका और दुर्गम क्शेत्तर, आबादी का घनत्व कम होना एवं जनजातीय आबादी का अधकि होना, पड़ोसी देशों से लगे (अंतरराष्ट्रीय सीमा) सामरिक क्शेत्तर में स्थिति होना, आर्थिक एवं आधारभूत संरचना में पछिड़ा होना और राज्य की आय की प्रकृति का नधिरति नहीं होना शामिल था। पूर्व में राष्ट्रीय वकिस परषिद द्वारा नरिधरति प्रावधानों के अनुसार सामरिक महत्त्व की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थिति ऐसे पहाड़ी राज्यों को वशेष श्रेणी राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता था जनिसे पास स्वयं के संसाधन स्रोत सीमति होते थे।

इन 11 पहाड़ी राज्यों को मलिा है वशेष दर्जा

- फलिहाल देश के 11 राज्यों को वशेष दर्जा मलिा हुआ है--अरुणाचल प्रदेश, असम, मणपुर, मेघालय, मजोरम, नगालैंड, सकिक्मि, त्रपुरा, जममू-कशमीर, हमिाचल प्रदेश और उत्तराखंड।
- जममू-कशमीर, असम और नगालैंड को 1969 में, हमिाचल प्रदेश को 1971 में, मणपुर, मेघालय और त्रपुरा को 1972 में, सकिक्मि, अरुणाचल प्रदेश और मजोरम को 1975 में तथा उत्तराखंड को 2001 में वशेष श्रेणी राज्य का दर्जा मलिा।
- अब तक देश में जनि राज्यों को वशेष श्रेणी राज्य का दर्जा मलिा है, उसके पीछे मुख्य आधार उनकी दुर्गम भौगोलिक स्थिति एवं वहाँ व्याप्त सामाजिक-आर्थिक वषिमताएँ हैं।
- इन राज्यों में अत्यधकि दुर्गम पहाड़ी क्शेत्तर होने और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थिति होने के कारण उद्योग-धंधे लगाना मुशकलि है।
- इन राज्यों में बुनयािदी ढाँचे का अभाव है और ये सभी आर्थिक रूप से भी पछिड़े हैं। वकिस के मामले में भी ये राज्य पछिड़े हुए हैं।

क्या लाभ होता है?

- इन मापदंडों को पूरा करने वाले राज्यों को केंद्रीय सहयोग के तहत प्रदान की गई राशा में 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण होता है।
- अन्य राज्यों को केंद्रीय सहयोग के तहत 70 प्रतिशत राशा ऋण के रूप में और 30 प्रतिशत राशा अनुदान के रूप में दी जाती है।
- वशेष श्रेणी राज्य का दर्जा देने के बाद केंद्र सरकार ने इन राज्यों को वशेष पैकेज सुवधि और टैक्स में कई तरह की राहत दी है।
- इससे नजिी क्शेत्तर इन इलाकों में नविश करने के लिये प्रोत्साहति होते हैं जसिसे क्शेत्तर के लोगों को रोजगार मलिता है और उनका वकिस सुनश्चिति होता है। संवधिान के 12वें भाग के पहले अध्याय में केंद्र-राज्यों के वत्तितीय संबंधों का उल्लेख है।

संवधिान क्या कहता है?

- हमारे संवधिान में किसी राज्य को वशेष श्रेणी राज्य का दर्जा देने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन देश के कुछ हसिसे अन्य राज्यों की तुलना में संसाधनों के मामले में पछिड़े हुए हैं, इसलिये ऐसे राज्यों को केंद्र ने वशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया है।
- राष्ट्रीय वकिस परषिद कम जनसंख्या घनत्व या बड़ा आदवािी बहुल इलाका, पहाड़ी और दुर्गम क्शेत्तर, अंतरराष्ट्रीय सीमा, कम प्रतवियकृति

आय और गैर कर राजस्व की कमी के आधार पर ऐसे राज्यों की पहचान करती है।

- संविधान के भाग 21 के अनुच्छेद 371 से लेकर 371J तक 12 राज्यों (यथा-महाराष्ट्र, गुजरात, असम, नगालैंड, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिकिम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और गोवा के बारे में विशेष प्रावधान किये गए हैं।

(टीम दृष्टि इनपुट)

वर्ष 1956 के संविधान के अंतर्गत राज्यों का पुनर्गठन

- संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर विशेष दर्जा (Special Status) प्राप्त भारत का एकमात्र राज्य है।
- विशेष राज्य का दर्जा संसद के दोनों सदनों में दो-तर्फी बहुमत से पारित अधिनियम के ज़रिये भारत के संविधान में किया गया प्रावधान है।

अलग है जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा

जम्मू-कश्मीर भारत के अन्य राज्यों की तरह नहीं है क्योंकि इसे सीमित संप्रभुता प्राप्त है और इसीलिए इसे 1969 में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन जम्मू-कश्मीर ने भारत के अधिराज्य को स्वीकार करते हुए सीमित संप्रभुता हासिल की थी और अन्य देशी रियासतों की तरह भारत के अधिराज्य के साथ उसका वलिय नहीं हुआ था, इसलिये इसका विशेष दर्जा अन्य ऐसे राज्यों से कुछ अलग है, जिनमें विशेष श्रेणी के राज्यों का दर्जा मिला हुआ है।

- देश के अन्य राज्यों में लागू होने वाले केंद्रीय कानून इस राज्य में लागू नहीं होते। इसके लिये राज्य सरकार की सहमति होना ज़रूरी है।
- रक्षा, विदेश नीति, संचार और वित्त के मामलों में ही भारत सरकार का दखल होता है।
- केंद्र सरकार संघीय और समवर्ती सूची में आने वाले विषयों पर जम्मू-कश्मीर के लिये कानून नहीं बना सकती।
- इस विशेष दर्जे के कारण जम्मू-कश्मीर को कुछ ऐसी विधायी और राजनीतिक शक्तियाँ भी मिली हुई हैं, जो अन्य राज्यों को प्राप्त नहीं हैं।

क्यों दिया गया विशेष राज्य का दर्जा?

- यह एक सीमावर्ती पर्वतीय राज्य है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएँ चीन और पाकिस्तान से लगती हैं।
- इस क्षेत्र को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद देश विभाजन के समय से लगातार बना रहता है।
- पाकिस्तानी सेना द्वारा लगातार युद्धविराम का उल्लंघन।
- वर्ष 1982 में शेख अबदुल्ला की मृत्यु के पश्चात् राज्य में अस्थायित्व की स्थिति।
- उग्रवादियों और भारतीय सैनिकों के मध्य संघर्ष का क्षेत्र बना हुआ है।
- राज्य में अफसूपा लागू होना, जिससे पता चलता है कि यह एक अशांत क्षेत्र है।
- चीन (1962) और पाकिस्तान (1965, 1971, 1999) के साथ हुए युद्धों से राज्य की स्थिति कमज़ोर हो चुकी थी।
- संयुक्त राष्ट्र की भागीदारी से यह अंतरराष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन चुका था।

(टीम दृष्टि इनपुट)

- इसके अलावा उत्तर-पूर्व के नगालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिकिम एवं त्रिपुरा तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड क्षेत्रों के राज्यों का दर्जा प्राप्त है, जिसके तहत उन्हें केवल केंद्रीय वित्तीय और आर्थिक सहायता ही मिलती है।

गाडगलि फॉर्मूला

- तीसरी पंचवर्षीय योजना यानी 1961-66 तक और फिर 1966-1969 तक केंद्र के पास राज्यों को अनुदान देने का कोई नश्चिन्ता फॉर्मूला नहीं था।
- उस समय तक केवल योजना आधारित अनुदान ही दिये जाते थे।
- 1969 में केंद्रीय सहायता का फॉर्मूला बनाते समय पाँचवें वित्त आयोग ने डी.आर. गाडगलि फॉर्मूले का अनुमोदन करते हुए तीन राज्यों को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया--असम, नगालैंड और जम्मू-कश्मीर।
- इसका आधार था इन राज्यों का आर्थिक पछिड़ापन, दूरह भौगोलिक स्थिति और वहाँ व्याप्त सामाजिक समस्याएँ।
- उसके बाद के वर्षों में पूर्वोत्तर के शेष पाँच राज्यों के साथ तीन अन्य राज्यों को भी यह दर्जा दिया गया।

क्या है डी.आर. गाडगलि फॉर्मूला?

विशेष श्रेणी के राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जो संसाधन बच जाते हैं, उन्हें 60% जनसंख्या के आधार पर, 25% राज्य की प्रतिव्यक्ति आय के आधार पर, 7.5% राजकोषीय प्रदर्शन के आधार पर और 7.5% इन राज्यों की विशेष परिस्थितियों के आधार पर वितरित किया जाता है।

(टीम दृष्टि इनपुट)

आंध्र प्रदेश के तर्क

- आंध्र प्रदेश ने विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा देने की मांग के पीछे तर्क यह दिया है कि हैदराबाद को तेलंगाना की राजधानी बनाने के बाद इसे राजस्व का काफी नुकसान हुआ है।

- हैदराबाद से अवभाजति आंध्र प्रदेश को लगभग 75,000 करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व प्राप्त होता था ।
- आंध्र प्रदेश का यह तर्क है कि उसे पोलावरम परियोजना और नई राजधानी अमरावती के लिये भी वित्तीय सहायता चाहिये ।

दिया जाना था विशेष दर्जा

तत्कालीन केंद्र सरकार ने राज्य के वभाजन के बाद आंध्र प्रदेश के सभी क्षेत्रों, विशेषकर सीमांध्र की समस्याएँ दूर करने के लिये विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा देने की बात कही थी, जिससे वपिकष का भी समर्थन प्राप्त था ।

- राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिये केंद्रीय सहायता के तहत 13 ज़िलों वाले आंध्र प्रदेश को पाँच वर्ष की अवधि हेतु विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा देने की बात कही गई थी जिसमें चार ज़िले रायलसीमा के और तीन ज़िले उत्तर तटीय आंध्र के थे ।
- राज्य पुनर्गठन वधियक में नरिधारति कथिया गया था कि केंद्र सरकार वभाजन के बाद दोनों राज्यों में औद्योगीकरण और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिये कर छूट सहित समुचित राजकोषीय उपाय करेगी । यह छूट कुछ अन्य राज्यों को दी जा रही छूट की तरह ही होगी ।
- वधियक में यह भी व्यवस्था की गई थी कि शेष आंध्र प्रदेश के पछिड़े क्षेत्रों, विशेष रूप से रायलसीमा और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश के जिलों में विशेष विकास पैकेज उपलब्ध कराया जाएगा । यह विकास पैकेज ओडिशा में K-B-K (कोरापुट-बलांगीर-कालाहांडी) विशेष योजना तथा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड विशेष पैकेज की तरह का था ।
- पोलावरम परियोजना के तहत सुगम और पूर्ण पुनर्वास और पुनर्स्थापना के लिये अन्य संशोधन यदि आवश्यक हुए तो उन्हें शीघ्र प्रभावी करने की बात कहते हुए केंद्र सरकार ने पोलावरम परियोजना नषिपादति करने की बात कही थी ।
- नए राज्य बनाने के लिये दनि अधिसूचति तथिसे संबंधति इस तरह से नयित कथिया जाना था कि कार्मिक, वतित और परसिंपत्तयिों एवं देनदारयिों के वतितरण के संबंध में तैयारी करने का काम संतोषजनक ढंग से पूरा कथिया जा सके ।
- वभाजन के बाद शेष आंध्र प्रदेश में पहले वर्ष, विशेषकर नयिकृति दनि और भारत सरकार द्वारा 14वें वतित आयोग की सफिरशिं स्वीकार करने की अवधि के दौरान होने वाले संसाधन के अंतर की पूर्ति 2014-15 के लिये नयिमति बजट में की जानी थी ।

(टीम दृष्टि इनपुट)

अब क्या कहती है केंद्र सरकार?

- केंद्र सरकार का कहना है कि वह राज्य के लिये विशेष आर्थिक पैकेज तो दे सकती है, लेकिन विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता ।
- हाल ही में केंद्रीय वतित मंत्री अरुण जेटली ने आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा न देने के पीछे 14वें वतित आयोग की रपिर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि इस रपिर्ट की सफिरशिं लागू होने के बाद अब किसी को भी विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता ।

वतित आयोग क्या है?

संवधान के अनुच्छेद-280 के तहत वतित आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पाँच साल या जरूरत होने पर इससे पहले भी कथिया जाता है । इस अनुच्छेद के तहत आयोग को केंद्र और राज्यों के बीच करों के बँटवारे को तय करने का काम दथिया गया है । साथ ही, संचति नधिसे भी राज्यों को अनुदान देने के संबंध में यह आयोग अपनी सफिरशिं देता है । इनके अलावा यदि राष्ट्रपति उसे वतितीय मुद्दों को लेकर कोई अतरिकित ज़मिमेदारी सौंपते हैं तो उन पर भी आयोग अपनी रपिर्ट सौंपता है । वतित आयोग अधनियिम, 1951 के तहत आयोग को अपने कर्तव्य के पालन में गवाहों को समन जारी करने, किसी दस्तावेज़ को प्रकट करने इत्यादि के संबंध में सविलि कोर्ट की सभी शक्तयिों प्राप्त होती हैं ।

(टीम दृष्टि इनपुट)

- आंध्र प्रदेश बंटवारे के खिलाफ था जबकि तैलंगाना वभाजन चाहता था; और जब राज्य का वभाजन हुआ तो आंध्र को संसाधनों की हानि उठानी पड़ी । इसलिये आंध्र प्रदेश को कुछ अतरिकित मदद देने के लिये विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे का वादा कथिया गया था ।
- तब विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे का वधिार अस्तित्व में था, लेकिन 14वें वतित आयोग के मुताबकि अब ऐसा कोई दर्जा नहीं दिया जा सकता ।
- वदिति हो कि इससे पहले भी वतित मंत्री ने कहा था कि चूँकि 14वें वतित आयोग द्वारा केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों का हसिसा 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दथिया गया है जिससे सभी राज्यों को पहले की तुलना में केंद्र से 50 प्रतिशत अधिक अंतरण प्राप्त होगा इसलिये अब विशेष दर्जे वाले राज्यों की जरूरत नहीं रह गई है ।
- 14वें वतित आयोग के मुताबकि जनि राज्यों को राजस्व में घाटा हो रहा था, उन्हें मुआवज़ा देने की बात की गई थी और आंध्र प्रदेश के मामले में राजस्व घाटे को लेकर सभी प्रावधानों को पूरा कथिया जा चुका है ।

राज्यों के पछिड़ेपन और विशेष सहायता पर रघुराम राजन समति की रपिर्ट

- जब बहिर ने अपने लिये विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा माँगा तो केंद्र सरकार ने रघुराम राजन समति का गठन कथिया ।
- इस समति से वभिनिन मानदंडों का इस्तेमाल कर पछिड़े राज्यों की पहचान के लिये तरीके सुझाने को कहा गया था ।
- इस समति ने 2013 में अपनी रपिर्ट दी, जिसमें आर्थिक रूप से पछिड़े राज्यों को अतरिकित सहायता देने के लिये उन्हें विशेष दर्जा देने वाले मापदंडों को समाप्त कर देश के 28 राज्यों को सबसे कम वकिसति, कम वकिसति और अपेक्षाकृत वकिसति राज्यों की श्रेणी में बाँटने का सुझाव दथिया था ।

- इस समिति ने राज्यों को धन देने के लिये एक नई प्रणाली सुझाई थी जो बहुआयामी सूचकांक प्रणाली पर आधारित थी।
- इस सूचकांक के आधार पर ही राज्यों को उपरोक्त तीन श्रेणियों में बांटा गया था।
- यह सूचकांक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा मापी गई प्रतिव्यक्ति खपत और गरीबी अनुपात जैसे मापदंडों पर आधारित था।
- समिति ने इस सूचकांक पर जनि राज्यों के अंक 0.6 या उससे अधिक हों उन्हें सबसे कम विकसित, 0.6 से कम लेकिन 0.4 से ज़्यादा अंक वाले राज्यों को कम विकसित और 0.4 से कम अंक वाले राज्यों को अपेक्षाकृत अधिक विकसित वर्ग में डालने की सफ़ारिश की थी।

(टीम दृष्टि इनपुट)

नबिकरष: केंद्र सरकार से योजना सहायता के उद्देश्य से उपरोक्त 11 हमिलयी तथा पर्वतीय राज्यों को वशेष श्रेणी वाले राज्यों का दरजा दिया गया है। यह राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धिदर, राज्यों में बचत और नविश दर, उत्पादकता में वृद्धि, व्यापारिक जलवायु, मानवीय विकास, आधारभूत सुवधियों की स्थिति और वभिन्न योजनाओं द्वारा संसाधनों के हस्तांतरण से जुड़े राज्य सरकार के प्रयास सहित कई घटकों पर नरिभर है। वशेष श्रेणी राज्य का दरजा मलिने से विकास योजनाओं के लाभ और नविश के लिये अनुकूल माहौल बनाने में भी सहायता मलिती है। लेकिन इसके बावजूद इन राज्यों में विकास की वह रफ़्तार देखने को नहीं मलिती जिसके लिये इन्हें यह दरजा दिया गया था। इसका कारण योजनाओं का समय पर पूरा नहीं हो पाना है।

इस मुद्दे पर हो रही राजनीति संसद पर भारी पड़ी। लगभग दो दर्जन वधियक संसद से पारति होने की बाट जोह रहे हैं, लेकिन वशेष राज्य के मुद्दे पर लगातार चल रहे गतरौध के चलते इन पर तथा ऐसे ही अन्य जनहति के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई। यहाँ तक कि अब तक के संसदीय इतहास में वतित वधियक पहली बार बना चर्चा के पारति हो गया। उल्लेखनीय है कि नए वतित वर्ष में बजट प्रावधानों को लागू करने के लिये इसका पारति होना ज़रूरी होता है।

वर्तमान मामले में आंध्र प्रदेश को वशेष राज्य का दरजा देने के बजाय केंद्र ने उसे वशेष राज्यों के बराबर वतित सहायता देने की बात कही है। वशेष श्रेणी के राज्य की अवधारणा आंध्र प्रदेश के वभिजन से पहले लागू थी, लेकिन 14वें वतित आयोग ने उसे समाप्त कर दिया। राज्य के वभिजन के बाद जनि संस्थानों के गठन को लेकर आंध्र प्रदेश के साथ वादा कया गया था, वह प्रक्रिया जारी है। वैसे भी आंध्र प्रदेश को वशेष दरजा देना बरर के छत्ते को छेड़ने जैसा होगा और इससे राज्यों के बीच एक नई होड़ शुरु हो जाएगी।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/special-category-state>

